*बिजनेस स्टैंडर्ड, सर्वोत्तम बी-स्कूल परियोजना पुरस्कार समारोह**

ऊर्जित आर. पटेल

यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आज मैं बिजनेस स्टैंडर्ड सर्वोत्तम बी-स्कूल परियोजना पुरस्कार का हिस्सा बना हूँ जो भारत में बिजनेस स्कूलों के प्रखर युवा प्रतिभाओं की पहचान के लिए आयोजित किया गया है। मुझे बताया गया है कि यह सातवां पुरस्कार समारोह है, और इसमें पूरे देश से विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं लेकर 158 महाविद्यालयों ने भाग लिया है। इससे पता चलता है इस पुरस्कार की कितनी अधिक महत्ता है, यह बी-स्कूल स्नातकों में कितना प्रसिद्ध है, और पिछले वर्षों में युवा पेशेवर प्रतिभाओं की पहचान करने एवं उन्हें सम्मानित करके इसने कितना अधिक प्रभाव डाला है, टीमों का चयन उनके कठिन परिश्रम, नवोन्मेषी दृष्टिकोण, विषय की संरचना तथा विभिन्न व्यावसायिक, सामाजिक तथा संगठनात्मक चुनौतियों के लिए उनके द्वारा बताए जाने वाले सार्थक समाधान के आधार पर किया जाता है।

यह समारोह 'बॉक्स से बाहर' की सोच का प्रतीक है और 'युवा भारत' की उद्यमिता कौशल को प्रदर्शित करता है। यह तरुण पेशेवरों की जाति है जो जोखिम उठाना जानती है और उनमें भविष्य में छलांग लगाने की आग है।

सच तो यह है कि मेरे सामने जो युवा विद्यार्थी बैठे हैं उन्हें देखकर मुझे अत्यधिक ईर्ष्या हो रही है। इनके भीतर स्वप्न हैं, इच्छाएं हैं और नए कारोबारी मॉडल तथा आधुनिक उद्यम तैयार करने की क्षमता है, जिसकी आज भारत को जरूरत है। इन्हें परस्पर जोड़कर आगे बढ़ाने वाले कई उल्लेखनीय उपकरण हैं जिन्हें हाल में बड़ी मेहनत से प्रारंभ किया गया है, जो हमारे तरूण स्नातकों के भीतर की प्रतिभा को निखारने में मदद करेंगे।

- समाधान प्रस्तुत करने के लिए उद्यमिता पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि प्रतिमाह एक मिलियन की श्रमशक्ति वृद्धि को खपाने के लिए अधिक से अधिक उद्यमियों, यदि सैकड़ों हजार नहीं तो दसियों हजार या उससे अधिक की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय उद्देश्य है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण का केंद्र बनाया जाए और भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग हो। 'भारत में निर्मित' का विजन/रणनीति प्रासंगिक है और यह हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में टिकाऊ प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए केंद्र-बिंदु की आवश्यकता को पूरा करेगा।
- 'कारोबार करने के सूचकांक को आसान' बनाने में भारत की रैंकिंग को बेहतर बनाने पर जोर। यह हमें यह मापने का तरीका प्रदान करता है कि हम कितनी प्रगति कर रहे हैं। 'नीति द्वारा संचालित' अभिशासन प्रक्रिया और कम सरकारी हस्तक्षेप को गहन बनाने के लिए वचनबद्धता दुहराई जा रही है और उससे जुड़े आधारगत परिवर्तन किए जा चुके हैं, जो आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण मिशन है।
- कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे कोयला और स्पेक्ट्रम में व्याप्त अनिश्चितता को समाप्त कर दिया गया है।
- आज की दुनिया में कुछ शब्दावली जैसे 'खेल का रूख बदलने वाला' और 'कायाकल्प करना' बहुत हलके में इस्तेमाल किया जाता है इसलिए ये अपेक्षित के बजाय सर्वत्र के अर्थ में अधिक प्रयोग किए जा रहे है। किंतु 'जन-धन योजना' पूरी तरह से हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लागू की गई है, जिसके अंतर्गत ऐसे लोगों के 100 मिलियन बैंक खाते खोले गए हैं जिनके पास बैंक खाते नहीं थे, यह स्थिति साफ-साफ 'खेल का रूख बदलने' जैसी ही है। इससे अप्रत्याशित मंच तैयार हुआ है और यह वित्तीय समावेशन के लिए एक सार्थक स्प्रिंगदार फलक साबित हुआ है तथा इससे सहगामी रूप से हमारी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक वित्तीय गहनता पैदा हुई है।
- हाल ही में, पुणे में बैंकरों एवं उच्च-स्तरीय नीति-निर्माताओं के 'ज्ञान-संगम' आयोजन में महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तनों के विषय में चर्चा की गई है। मैं उनमें

* डॉ. ऊर्जित आर. पटेल, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 12 जनवरी 2015 को वेलिंगकर प्रबंधन विकास संस्थान में दिया गया व्याख्यान।

से वस्तुतः वास्तविक वेबसाइट से दो का संदर्भ संक्षेप में देना चाहता हूँ :

- o हमें प्रभावी रूप से उधार देने के तरीकों को पुनः परिभाषित करना होगा, अर्थात् ऐसे उद्यमों को प्राथमिकता आधार पर ऋण प्रदान करना जो रोजगार के अधिक अवसर पैदा करें।
- o सुस्त बैंकिंग को अलविदा कहना : बैंकों से कहा गया है कि वे आम आदमी की सहायता करने में सक्रिय भूमिका अदा करें।

दूसरे शब्दों में, जैसे-जैसे हम इस दिशा में आगे बढ़े, बैंकजन्य श्रम-उन्मुख उद्यमों को फायदा मिलना चाहिए ।

इसके लिए 3 संभाव्य तरीके हैं :

(i) प्रथम, भारी संख्या में छोटे-छोटे कारोबार को ऋण देने को प्रोत्साहित किया जाए बजाय बहुत बड़े-बड़े ऋण देने पर ज़ोर देने के।

(ii) दूसरा, प्राथमिकता क्षेत्र नीति/दिशानिर्देश पर हुई चर्चा के संदर्भ में, छोटे उद्यमियों, एसएमई तथा रोजगार सृजन के लिए वित्त प्रदान किए जाएं (भारतीय रिज़र्व बैंक की छोटे वित्त बैंकों के लिए लाइसेंसीकरण नीति में प्राथमिकता क्षेत्र को अधिक एक्सपोज़र देने की शर्त रखी गई है)।

(iii) तीसरा, बैंक यथासमय जब भी सही समय मिले (अभी नहीं) (अर्थात् भविष्य में) प्रत्येक कंपनी / समूह को दिए गए ऋण की राशि सीमा, तथा क्षेत्र के एक्सपोज़र पर पुनः दृष्टि डालें ताकि वे भविष्य में कारोबारी चक्र में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी हासिल कर सकें।

- अंतिम बात, बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त की गई मैक्रो-आर्थिक स्थिरता सभी हितधारकों के लिए इष्टतम निर्णय लेने में महत्वपूर्ण परिदृश्य उपलब्ध कराती है। हमें इसे बनाए रखना है। तेल की कीमतों में जिस ड्रामाई तरीके से गिरावट आई है वह हमारे लिए वरदान साबित हुई है। वार्षिक आधार पर देखें तो इससे लगभग 50 बिलियन अमरीकी डालर की बचत होगी, मोटे तौर पर जो हमारे प्रतिवर्ष पेट्रोलियम, तेल, चिकनाई के आयात पर खर्च होने वाली कुल राशि 160 बिलियन अमरीकी डालर का एक-तिहाई है। यह लिफाफे के पीछे प्रमुखता से लिखी गई बात है। निश्चित रूप से इसमें कुछ लीकेज एवं अन्य समायोजन होंगे। किंतु हमारी बाह्य स्थिति में निःसंदेह सुधार हुआ है। इस प्रकार की प्रगति स्वागत योग्य है, इससे हमारी निपटान योग्य आय में वृद्धि होगी (जिससे उपभोक्ता की अन्य सामग्री एवं सेवा के लिए मांग बढ़ेगी), हमारे कारोबार की इनपुट लागत कम होगी (इससे मार्जिन बढ़ेगा जो निवेश की मांग को आगे बढ़ाएगा), और इससे बजट में सब्सिडी का बोझ घटेगा और सरकारी वित्त को सहायता मिलेगी।

मैं अपनी बात इस वर्ष के गतिमान गुजरात वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में एक सहभागी द्वारा कही गई बात से समाप्त करना चाहूँगा, 'भारत अन्यथा रूप से मेडियोकर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक चमकदार स्थल होगा'।

एक बार पुनः मुझे सातवें बिजनेस स्टैंडर्ड सर्वोत्तम बी-स्कूल परियोजना पुरस्कार समारोह में वक्तव्य देने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।